असम

भारत के पूर्वोत्तर प्रवेशद्वार में डिजिटल उत्कृष्टता का नेतृत्व

संपादित : **विनोद कुमार गर्ग**

असम, जीवंत पूर्वोत्तर राज्य, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपनी चाय, एक सींग वाले गैंडे और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जाना जाता है, देश में डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और प्रशासन के सभी स्तरों पर बेहतर शासन प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग कर रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सरकार का सबसे विश्वसनीय और प्रमुख प्रौद्योगिकी भागीदार रहा है, जो प्रशासनिक दक्षता को मज़बूत करने और सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए संपूर्ण डिजिटल समाधानों को सशक्त बनाता है। एनआईसी असम राज्य केंद्र ने 1986 से कार्य करना शुरू किया, और नब्बे के दशक के मध्य तक, राज्य के प्रत्येक जिले में एनआईसी की एक जिला इकाई थी। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध में ऑनलाइन तकनीकों के आगमन ने असम और एनआईसी को इस स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया।

राज्य सरकार ने अपने विज़न में डिजिटल नवाचारों को सक्रिय रूप से अपनाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी-संचालित शासन असम के हर कोने तक, शहरी केंद्रों से लेकर दूरदराज के गाँवों तक पहुँचे। इस विज़न को साकार करने के लिए एनआईसी ने कदम बढ़ाया। डिजिटल इंडिया के विज़न के साथ अपनी प्रगति को संरेखित करते हुए, असम और एनआईसी ने ई-गवर्नेंस समाधानों, संपर्क रहित नागरिक सेवाओं, डेटा-संचालित डैशबोर्ड से लेकर अगली पीढ़ी के बुनियादी ढाँचे और स्वचालन तक, विभिन्न सरकारी विभागों में व्यापक डिजिटल पहलों को लागू करने के लिए हाथ से हाथ मिलाया। एनआईसी असम ने स्केलेबल आईटी समाधान विकसित करने, मज़बूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा स्थापित करने और राज्य की डिजिटल यात्रा का समर्थन करने वाली तकनीकी रीढ़ के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए नवीन अनुप्रयोगों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रुबाइयात उल अली
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
rubaiyat@nic.in

मैत्रेयी सरमा
वैज्ञानिक - बी व एसएमसी
maitreyee.sarma@nic.in

> असम भारत में डिजिटल नवाचार में सबसे आगे है, और एक अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-हितैषी सरकार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। 1986 से मिलकर काम करते हुए, एनआईसी असम राज्य केंद्र और राज्य सरकार ने विविध आईसीटी पहलों के साथ एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है, जिसने लाखों नागरिकों के जीवन को बदल दिया है।

असम के डिजिटल परिवर्तन में एनआईसी की भागीदारी का पैमाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। असम की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलों का एक बड़ा हिस्सा एनआईसी द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। इनमें 29 राज्य-विशिष्ट परियोजनाएँ, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप 12 राष्ट्रीय परियोजनाएँ, और सेवाओं एवं सुरक्षा ढाँचों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की स्थापना शामिल है।

राज्य में आईसीटी पहलें

पंचायत मतदाता सूची और चुनावों का डिजिटलीकरण

लोकतंत्र की नींव पारदर्शी और कुशल चुनावी प्रक्रियाओं में निहित है। हालाँकि, यह नींव पुरानी और बोझिल मैनुअल प्रणालियों की अस्थिर नींव पर खड़ी थी। ऑनलाइन मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली (ओ. ई. आर. एम. एस.), चुनाव प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, और मतदान कार्मिक प्रबंधन प्रणाली (पी. पी. एम. एस.) ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। इसने संपूर्ण मतदाता सूची तैयार करने और मतदान प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। इस प्रणाली ने 2,192 गाँव पंचायतों और 25,046 मतदान केंद्रों को कवर किया है, जिनमें 18,091,705 मतदाता नामांकित हैं। चुनावों के दौरान, इस प्लेटफ़ॉर्म ने आंचलिक पंचायत और जिला परिषद पदों के लिए 7,174 नामांकन संसाधित किए, 6,610 स्वीकार किए, 179 अस्वीकृत किए और 385 नाम वापस लिए। इस सरकार-से-सरकार (जी 2 जी) पहल ने असम में जमीनी स्तर के लोकतंत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाई है।

सीएम डैशबोर्ड

सीएम डैशबोर्ड राज्य के शीर्ष नेतृत्व के लिए सरकारी प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन हेतु एक अभिनव दृष्टिकोण है। यह अनूठा एपीआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म ज़िलों की वास्तविक समय, डेटा-आधारित निगरानी और प्रदर्शन मूल्यांकन को सक्षम बनाता है, गतिशील, स्वचालित डेटा संग्रह के माध्यम से वास्तविक आंकड़ों के साथ सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ज़िलों को पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करता है।

यह डैशबोर्ड 43 केंद्रीय योजनाओं, 37 राज्य योजनाओं और 1 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की निगरानी करता है, जिसमें 17 संग्रहीत योजनाओं के साथ 38 परियोजनाएँ शामिल हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यान्वयन प्रगति पर नज़र रखने और वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर सूचित निर्णय लेने का एक अनिवार्य उपकरण है।

सेवा सेतु

सेवा सेतु असम के प्रमुख नागरिक सेवा मंच के रूप में प्रतिष्ठित है, जो 20 से अधिक पोर्टलों और उमंग, आधार, ई-प्रमाण और

डिजिलॉकर सहित 10 राष्ट्रीय प्लेटफार्मों को एकीकृत करके अभूतपूर्व 815 सेवाएँ प्रदान करता है। इस सरकार-से-नागरिक (जी 2 सी) मंच ने 1.94 करोड़ आवेदनों का प्रसंस्करण किया है, जिनमें से 1.75 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है।

इस मंच में एक एकीकृत अपील और शिकायत प्रबंधन प्रणाली शामिल है और यह कुशल बैक-एंड वर्कफ़्लो प्रबंधन के लिए एक इन-हाउस सेवा फ़्लोमास्टर का लाभ उठाता है। सुगम्यता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, सेवा सेतु डब्ल्यूसीएजी और जीआईजीडब्ल्यू 3.0 मानकों का अनुपालन करता है, जिसमें यूएक्स4जी द्वारा डिज़ाइन किया गया सुगम्यता मेनू शामिल है। इस मंच की तकनीकी संरचना मापनीयता के लिए माइक्रोसर्विसेस और सुरक्षित निरंतर एकीकरण और परिनियोजन के लिए डेवसेकऑप्स का लाभ उठाती है, जो इसे नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन के लिए एक आदर्श बनाती है।।

ई.ओ.डी.बी.

व्यापार सुगमता मंच ने असम को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी) की ई.ओ.डी.बी. रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान दिलाया है। यह एकीकृत जी2सी मंच 21 विभागों और 42 उप-विभागों में 300 से अधिक ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है - 273 अंत-से-अंत और 27 बाहरी सेवाएँ।

इस मंच ने 26.65 लाख सेवाएँ प्रदान की हैं जिनकी निपटान दर 98.28% है। इस प्रणाली ने 3.4 लाख सामान्य आवेदन पत्र पंजीकृत किए हैं और 27.12 लाख आवेदनों का प्रसंस्करण किया है, जिससे व्यावसायिक अनुमोदन और मंज़ूरी प्राप्त करने में लगने वाले समय और जटिलता में उल्लेखनीय कमी आई है।

ई-प्रस्तुति

असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ई-प्रस्तुति के माध्यम से सरकारी वेबसाइटों के लिए एक मानकीकृत वेबसाइट ढाँचा लागू किया है। इस पहल ने सरकार की वेब उपस्थिति को मानकीकृत किया है, जिससे सभी आधिकारिक वेबसाइटों पर डिज़ाइन, पहुँच संबंधी सुविधाओं और सूचना संरचना में एकरूपता सुनिश्चित हुई है, जिससे सरकारी जानकारी अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो गई है। ई-प्रस्तुति 299 वेबसाइटों को कवर करती है, जिनमें विभागों, जिलों, राज्य पोर्टल और राज्यपाल पोर्टल की वेबसाइटें शामिल हैं।

ई-मंत्री सभा

ई-मंत्री सभा ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर निर्णयों की ट्रैकिंग और कार्यान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर असम में कैबिनेट शासन को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे कैबिनेट बैठकें 100% कागज़ रहित हो गई हैं।

यह प्रणाली डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी एस सी), ई-परिचय और आधार प्रमाणीकरण को सहजता से एकीकृत करती है, और भारत वी सी एकीकरण भी जारी है। कार्यान्वयन के बाद से, इस प्लेटफ़ॉर्म ने 181 बैठकों का संचालन किया है, 3,497 निर्णयों को रिकॉर्ड किया है, जिनमें संग्रहीत कैबिनेट निर्णय भी शामिल हैं, जिससे राज्य कैबिनेट की दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असोम अभियान

उद्यमिता के माध्यम से बेरोज़गारी की समस्या का समाधान करते हुए, मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असोम अभियान युवाओं को स्व-रोज़गार के अवसरों से सशक्त बनाने और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस जी 2 सी पहल के तहत 2,29,145 व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ है, 1,04,091 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और 25,000 से अधिक व्यक्तियों को अपना उद्यम शुरू करने में सहायता मिली है।

एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (आई.एल.आर.एम.एस.)

भूमि अभिलेख, संपत्ति अधिकारों और कृषि प्रशासन का आधार हैं। आई.एल.आर.एम.एस. ने भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रक्रियाओं को एकीकृत अनुप्रयोगों के एक व्यापक समूह के साथ डिजिटल कर दिया है, जिसमें बसुंधरा, धरित्री, भू-अभिलेख, ई-खजाना, चिट्ठा, स्वामित्व, लैंडहब, एन.जी.डी.आर.एस., सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण और आर.सी.सी.एम.एस. शामिल हैं। नागरिकों को ऑनलाइन जी 2 सी सेवाएँ सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

निर्माण सखी

निर्माण सखी निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाती है। यह दावों (क्लेम) की पारदर्शी प्रक्रिया, सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा भुगतान, मानक के अनुसार सेस आकलन, और श्रमिक कल्याण सेवाओं को सरल तरीके से प्रदान करती है। यह असम के निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम विभाग के तहत काम करती है।

आधार वॉल्ट से जुड़ने वाला यह पहला आवेदन है। अभी तक इसके तहत कुल 1,35,387 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 96,471 पंजीकरण (ऑनबोर्डिंग) आवेदन और 38,916 नए आवेदन शामिल हैं।

ऐसा माना जाता था कि असम में इस तरह का काम नहीं हो सकता। हमने धीरे-धीरे शुरुआत की है। परिवहन विभाग की (संपर्क रहित) सेवाओं से सात लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन परिवहन में यह संख्या बढ़ती ही जाएगी और 2026 तक इस पूरी प्रक्रिया से लगभग एक करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। असम में रैंडमाइजेशन (उनके द्वारा विकसित सीएम-ट्रांस एप्लिकेशन का संदर्भ देते हुए) देश में पहला है। अगर कोई इसे अभी करना चाहता है, तो वह असम मॉडल होगा। इस काम के परिणामस्वरूप, हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। एनआईसी असम ने हमारे लिए यह कार्यक्रम किया है। उन्होंने इसे पहली बार किया है और एनआईसी असम हमारे अनुरोधों का जवाब देने में वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं एनआईसी टीम के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हम सभी के लिए ये सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एनआईसी की तारीफ़ करें क्योंकि उनकी वजह से ही हम कई उपलब्धियाँ हासिल कर पाए हैं। हमें इन सॉफ़्टवेयर के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, न ही कोई बिल, अनुबंध या टेंडर है, हम बस इसे लागू कर रहे हैं क्योंकि एनआईसी हमारी मदद के लिए है और हम यह कर रहे हैं।

श्री हिमंता बिस्वा सरमा
असम के माननीय मुख्यमंत्री
(असम में संपर्क रहित परिवहन सेवाओं के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री के भाषण का अंश)

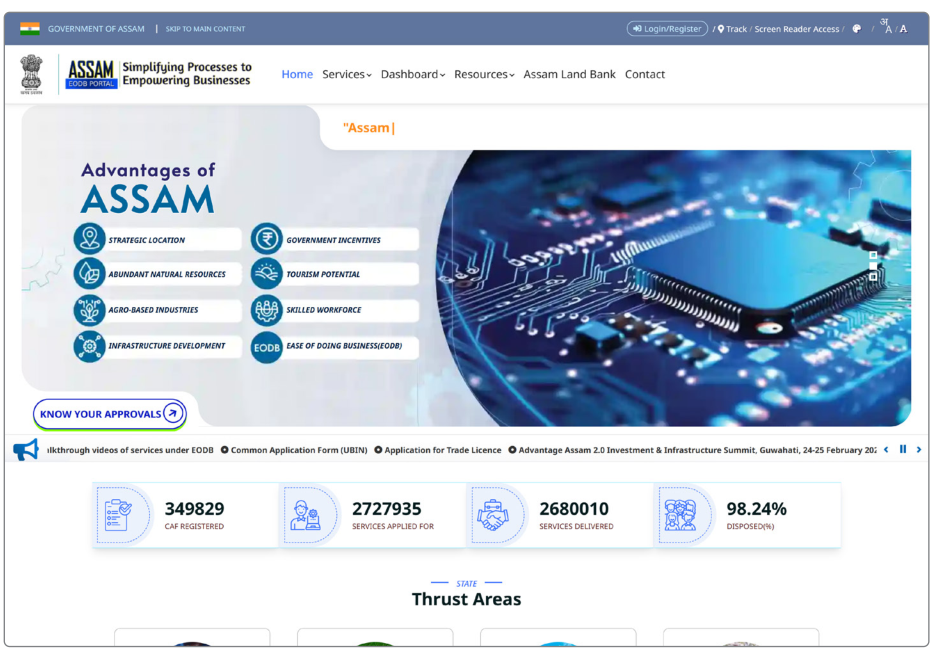

चित्र 1.1 : ई.ओ.डी.बी. वेबसाइट होमपेज

एनआईसी असम राज्य की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, जिसके दौरान असम के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई राज्य-विशिष्ट और राष्ट्रीय परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

एनआईसी के स्केलेबल आईटी समाधानों ने व्यापक डैशबोर्ड और अन्य ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं और डेटा-संचालित शासन को सक्षम बनाया है। 41 सक्रिय जी2सी, जी2ई और जी2बी अत्याधुनिक परियोजनाओं और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं—जिनमें निकनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनकेएन शामिल हैं—के साथ एनआईसी ने खुद को असम में एक प्रमुख आईसीटी स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। एनआईसी द्वारा विकसित गतिशील सीएम डैशबोर्ड का डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। निदेशालयों में ई-ऑफिस को अपनाने से सरकारी फ़ाइल प्रसंस्करण में बदलाव आया है, जबकि सेवा सेतु और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ई.ओ.डी.बी.) जैसे सेवा पोर्टलों ने नागरिकों को बहुत लाभान्वित किया है। असम को ई-परिवहन को लागू करने में एक अग्रणी राज्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जो इस महत्वपूर्ण राजस्व-अर्जन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।

हर ज़िले में एनआईसी केंद्रों के साथ, डिजिटल सेवाएँ अब दूर-दराज़ के गाँवों तक पहुँच रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। एनआईसी की साझेदारी ने असम को डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी बनाने में मदद की है। राज्य सरकार और एनआईसी ने एक बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए डिजिटल तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मिलकर काम किया है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डिजिटल रूप से सशक्त असम बनाने के लिए निरंतर सहयोग की आशा करते हैं।

डॉ. रवि कोटा, आईएएस
मुख्य सचिव, असम

असम ई-ग्रास

सरकारी रसीद लेखा प्रणाली (ई-ग्रास) नागरिकों और विभागों को असम सरकार की सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाती है, जिससे ई-चालान निर्माण, बहु-शीर्ष भुगतान और कोषागार एवं गैर-कोषागार दोनों शीर्षों के लिए रसीद लेखांकन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इस जी 2 जी/जी 2 सी प्लेटफ़ॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,05,69,390 ई-चालान उत्पन्न किए हैं, जिनसे कुल ₹84,446.97 करोड़ का संग्रह हुआ है।

डिजिटल आईटीआई प्लेटफ़ॉर्म

यह मानते हुए कि कुशल कार्यबल का विकास आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, डिजिटल आईटीआई प्लेटफ़ॉर्म औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए एक एकीकृत डिजिटल सुइट का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म में तीन एकीकृत घटक हैं: एक एमआईएस पोर्टल जो वास्तविक समय में शिक्षाविदों, छात्रों और प्रशासन पर नज़र रखता है; एक संबद्धता पोर्टल जो आईटीआई अनुमोदन और अनुपालन प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है; और एक ई-परामर्श पोर्टल जो निष्पक्ष, कागज़ रहित, योग्यता-आधारित आईटीआई प्रवेश को सक्षम बनाता है।

कृतज्ञता

कृतज्ञता ने पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाकर और बाधाओं को कम करके पेंशनभोगियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस जी2ई प्लेटफ़ॉर्म ने 59,722 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जोड़ा है, विभागाध्यक्षों द्वारा 55,610 मामलों का निपटान किया है और 51,552 पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) स्वीकृत किए हैं। 4,058 मामले पी पी ओ अनुमोदन के लिए लंबित हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म ने प्रभावशाली 92.70% पी पी ओ अनुमोदन दर बनाए रखी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बाद उनके पेंशन लाभ तुरंत और सम्मान के साथ प्राप्त हों।

ई-समीक्षा

ई-समीक्षा एक महत्वपूर्ण निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विभाग प्रमुखों द्वारा विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म ने माननीय मुख्यमंत्री की 215 बैठकों में 3,062 कार्य बिंदुओं, उपायुक्त सम्मेलन में 116 कार्य बिंदुओं, एचसीएम नोट्स में 395 कार्य बिंदुओं, एचसीएम भ्रमण निर्देश में 180 कार्य बिंदुओं और सीएम कॉन्क्लेव में 42 कार्य बिंदुओं को सुगम बनाया है। निगरानी के लिए यह व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णयों की स्पष्ट जवाबदेही तंत्र के साथ कार्यान्वयन के माध्यम से निगरानी की जाए।

ई-प्रयुक्ति सेवा

ई-प्रयुक्ति सेवा त्वरित, अनुकूलन योग्य और कुशल ऐप विकास के लिए वन-स्टॉप मोबाइल ऐप-निर्माण सेवा प्रदान करके जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। पंजीकरण, आवश्यकताओं को एकत्रित करने और वास्तविक समय सेवा स्थिति ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत पोर्टल की सुविधा के साथ, यह उपयोग में आसान प्रणाली विभिन्न विभागों को बिना किसी व्यापक तकनीकी विशेषज्ञता के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने में सक्षम बनाती है।

जलतरंगिणी

जलतरंगिणी आई ओ टी तकनीक के माध्यम से बाढ़ प्रबंधन और जल संसाधन निगरानी की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करती है। यह प्रणाली वास्तविक समय में जल स्तर की निगरानी करती है, नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों से RF/LoRa के माध्यम से डेटा प्रसारित करती है और महत्वपूर्ण सीमाओं पर अलर्ट जारी करती है। आईओटी-सक्षम RF/LoRa तकनीक पर निर्मित यह प्लेटफ़ॉर्म कॉपीराइट पंजीकृत है और एनआईसी असम द्वारा पेटेंट दायर किया गया है और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसे लागू करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रणाली ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, जिनमें उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एनआईसी इनोवेशन चैलेंज 2018 में स्वर्ण और जलवायु/आपदा लचीलापन के लिए ईटी डिजिटेक पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार शामिल हैं, जो पूर्व चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से जीवन और संपत्ति को बचाने की इसकी क्षमता को उजागर करता है।

असम नागरिक पुरस्कार

असम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के वितरण की सुविधा प्रदान करने वाली यह समर्पित ऑनलाइन प्रणाली, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पुरस्कार नामांकन को सुव्यवस्थित

▼ चित्र 1.2 : सेवा सेतु का सिस्टम आर्किटेक्चर

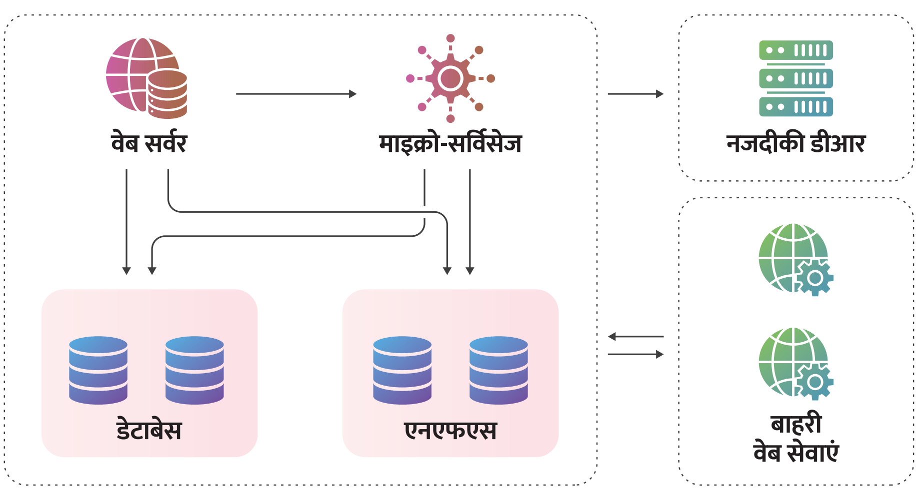

▲ चित्र 1.3 : सेवा सेतु वेबसाइट होमपेज

करती है। इस पोर्टल को 2023 में 90 और 2024 में 266 आवेदन प्राप्त हुए, जो अनुकरणीय नागरिकों को मान्यता देने में बढ़ती जन भागीदारी को दर्शाता है।

ड्रग्स फ्री असम

ड्रग्स फ्री असम एक मोबाइल ऐप है जो नागरिकों को नशीली दवाओं से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों, व्यक्तियों या परिवहन की सूचना पुलिस को देने के लिए सशक्त बनाता है। उपयोगकर्ता गुमनाम रूप से फोटोग्राफिक साक्ष्य और जीपीएस लोकेशन टैगिंग के साथ शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म को अब तक 1,624 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कानून प्रवर्तन प्रयासों में प्रौद्योगिकी-संचालित जन भागीदारी के माध्यम से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने में सामुदायिक भागीदारी को दर्शाता है।

सद्भावना

सद्भावना, फाइलों के त्वरित निपटान के लिए असम सरकार की एक प्रमुख पहल है। सद्भावना पोर्टल के माध्यम से सभी भौतिक फाइलों में लंबित मामलों का समाधान किया जाता है और फाइलों को बंद घोषित किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर 316 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 242 का निपटारा किया गया और 74 प्रक्रियाधीन हैं, जिससे 76.58% का प्रभावशाली निपटान दर बना रहा।

परीक्षा परिणाम

एनआईसी असम ने लगातार 12 वर्षों तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम (एच.एस.एल.सी. और एएचएम) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एच.एस.एस.एल.सी.) के परिणाम सफलतापूर्वक प्रकाशित किए हैं। परिणाम के दिन 23 लाख से अधिक वेबसाइट विज़िटर को संभाला है और जारी होने के बाद प्रति मिनट 12,000 हिट्स का प्रबंधन किया है, जो मजबूत बुनियादी ढांचे और मापनीयता का प्रदर्शन करता है।

चिकित्सा परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली

मेड-एएमएस ने चिकित्सा सुविधाओं में चिकित्सा परिसंपत्ति प्रबंधन को निर्बाध परिसंपत्ति प्रविष्टि, वास्तविक समय पारदर्शिता और विक्रेता एकीकरण के माध्यम से सुधारा और अनुकूलित किया है। परिसंपत्तियों की खरीद से लेकर निपटान तक ट्रैकिंग की जाती है जिससे उचित रखरखाव, उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित होता है। इसका उपयोग 16 चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में किया जाता है, जिसमें 3,408 प्रमुख परिसंपत्तियाँ (93% कार्यशील) और 44,227 लघु परिसंपत्तियाँ (92% कार्यशील) पंजीकृत हैं, जिससे चिकित्सा उपकरणों की जवाबदेही और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होता है।

शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार

यह मंच हर साल शिक्षक दिवस पर राज्य के असाधारण शिक्षकों को सम्मानित करता है। इसमें शिक्षकों के लिए एक सुव्यवस्थित 3-चरणीय व्यापक स्व-नामांकन प्रक्रिया, स्वचालित मूल्यांकन और पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन की सुविधा है, जिससे प्रशासन द्वारा निर्णय लेना आसान हो जाता है। इस जी2सी मंच को 2024 में 273 और 2025 में 427 आवेदन प्राप्त हुए, जिससे 2024 में 13 और 2025 में 15 पुरस्कार विजेताओं का चयन हुआ, जिससे राज्य भर में शिक्षण उत्कृष्टता को मान्यता मिली।

मत्स्य बैभव

असम की "घरे घरे पुखुरी, घरे घरे माछ" (जीजीपीजीजीएम)

यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग असम राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया में आईसीटी अनुप्रयोगों को शामिल करने के लिए लंबे समय से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ काम कर रहा है। 2022 के मध्य में, राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना था। यह कार्य आयोग के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, असम के सहयोग से किया गया। इस पहल के परिणामस्वरूप, प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बाद ऑनलाइन मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली (ओ. ई. आर. एम. एस.) का सफलतापूर्वक विकास किया गया। असम में पहली बार, आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिए ओ. ई. आर. एम. एस. का उपयोग किया और 1.80 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाली पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए आम चुनाव आयोजित किए।

ओ.ई.आर.एम.एस. के सफल विकास के बाद, आयोग ने एनआईसी असम के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आईसीटी अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला विकसित करने की पहल की। इनमें ई-निर्वाचन (मतदान और मतगणना कर्मियों के कम्प्यूटरीकृत याहच्छिकीकरण के लिए), मतपेटी प्रबंधन प्रणाली (मतपेटियों के कम्प्यूटरीकृत याहच्छिकीकरण के लिए), और चुनाव प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (शपथपत्रों के साथ उम्मीदवारों के नामांकन के डिजिटलीकरण के लिए) शामिल हैं। इन सभी अनुप्रयोगों का पहली बार राभा हसोंग स्वायत्त परिषद चुनाव में और बाद में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के आम चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। पीआरआई चुनावों के दौरान, 1 लाख से अधिक कर्मियों का याहच्छिक चयन किया गया और उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों पर आवंटित किया गया, 50,000 से अधिक मतपेटियों को याहच्छिक रूप से आवंटित किया गया, और 7,000 से अधिक नामांकन प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया।

उपरोक्त सभी आईसीटी अनुप्रयोगों को श्री रुबाइयात उल अली (वैज्ञानिक-एफ), एनआईसी, असम के नेतृत्व में उच्च योग्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की एक टीम और एक अनुभवी प्रबंधन समिति द्वारा विकसित किया गया था। इन अनुप्रयोगों का प्रबंधन एनआईसी असम के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) और अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (एडीआईओ) द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है, जो राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात हैं।

आयोग एनआईसी असम के प्रयासों की सराहना करता है और असम राज्य में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नए आईसीटी अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन की यात्रा जारी रखने की उम्मीद करता है।

श्री आलोक कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)
राज्य चुनाव आयुक्त, असम

▲ चित्र 1.4 : माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा परियोजना सद्भावना का शुभारंभ

योजना के अंतर्गत, मत्स्य परिसंपत्ति पोर्टल और मत्स्य बैभव मोबाइल एप्लिकेशन, जी. जी. पी. जी. जी. एम. के तहत बनाए गए सभी तालाबों और टैंकों की जीपीएस-आधारित जियो-टैगिंग के माध्यम से संपूर्ण डिजिटल संपत्ति मानचित्रण को सक्षम बनाता है। यह मज़बूत मोबाइल समाधान लाभार्थियों की जनसांख्यिकी, तालाबों के सटीक आयाम, भौगोलिक निर्देशांक और वास्तविक समय के फोटोग्राफिक दस्तावेज़ीकरण को व्यवस्थित रूप से कैप्चर करता है। इस एप्लिकेशन ने जी. जी. पी. जी. जी. एम. के अंतर्गत 9,083 तालाबों/टैंकों को सफलतापूर्वक कवर किया है, जिनमें से 9,029 को जियो-टैग किया गया है, 99% कार्य पूर्ण हो चुका है और सरकारी संपत्तियों की पारदर्शी निगरानी का प्रदर्शन किया है।

राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल

माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 22 अगस्त, 2022 को लॉन्च किया गया, एस.पी.पी.पी., असम सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2017 के तहत असम के एकीकृत निविदा पहुँच मंच के रूप में कार्य करता है। यह मंच असम निविदाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना "पी.एम.जी.एस.वाई., जीईएम और मैन्युअल निविदाओं को एकीकृत करता है, जिससे विभागों को एनआईटी, दस्तावेज़ और शुद्धिपत्र ऑनलाइन प्रकाशित करने में सक्षम बनाता है, साथ ही नागरिकों को निविदा विवरण और डैशबोर्ड तक स्वतंत्र रूप से पहुँच प्रदान करता है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

मानव संपदा

मानव संपदा, जिसका नाम मानव पूंजी के लिए उपयुक्त है, सरकारी क्षेत्र के लिए एक व्यापक आई सी टी समाधान प्रदान करता है, जो प्रमुख कार्मिक प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करता है। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लागू, इस जी 2 ई प्लेटफ़ॉर्म ने 3,126 सेवा पुस्तिकाएँ पंजीकृत की हैं, 5,696 अवकाश आवेदन प्राप्त किए हैं, और 2,109 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) तैयार की हैं, जिससे सरकारी विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन सुव्यवस्थित हुआ है।

नियुक्ति

नियुक्ति सरकारी विभागों के लिए एक सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर (SaaS) आधारित भर्ती समाधान है जिससे भर्ती अभियान चलाया जा सके। भर्ती एजेंसियाँ अधिकृत भर्तीकर्ताओं के रूप में शीघ्रता से शामिल हो सकती हैं और न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन के साथ भर्ती प्रक्रियाएँ शुरू कर सकती हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म तेज़, कुशल और पारदर्शी भर्ती प्रबंधन सुनिश्चित करता है। इसने 2,50,000 आवेदनों का प्रसंस्करण किया है, 900 से अधिक पदों पर 84 भर्ती पूरी की हैं, जिससे राज्य भर में सरकारी भर्तियाँ सुव्यवस्थित हुई हैं।

ई-डाक

ई-डाक मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आधिकारिक पत्रों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत, भूमिका-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। यह भूमिका-आधारित पहुँच और कार्यप्रवाह के साथ संचार की डायरीकरण, प्रबंधन और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली डायरीकृत और पुराने दोनों प्रकार के पत्रों को संभालती है, जिससे केंद्रीकृत ट्रैकिंग क्षमताओं के साथ सभी विभागों में सुव्यवस्थित पत्र प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

मातृ पितृ वंदना

2022 में शुरू की गई मातृ पितृ वंदना पहल, असम सरकार के कर्मचारियों को माता-पिता और सास-ससुर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए सालाना दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करती है। छुट्टी लेने के बाद, कर्मचारियों को विभाग प्रमुखों द्वारा अनुमोदित हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन और अवकाश अवधि के दौरान माता-पिता के साथ ली गई तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी, जिससे कर्मचारियों के बीच कार्य-जीवन संतुलन और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस परिवार कल्याण पहल की जवाबदेही और वास्तविक उपयोग सुनिश्चित होगा।

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल

प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, पेंशन और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया, सूचना का अधिकार ऑनलाइन पोर्टल आरटीआई अनुरोधों और प्रथम अपीलों को जमा करने और उन पर नज़र रखने के लिए एक पारदर्शी, कागज़ रहित मंच प्रदान करता है। आज तक rtionline.assam.gov.in को 2,812 आरटीआई अनुरोध और 527 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1,548 नागरिक पंजीकृत हैं और 1,313 सार्वजनिक प्राधिकरण इसमें शामिल हैं। सुरक्षित भुगतान के लिए ई-ग्रास के साथ एकीकृत, यह सूचना तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करता है और नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करता है।

रुर्बनसॉफ़्ट

रुर्बनसॉफ़्ट राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस में असम के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। पूरी तरह से असम में विकसित और सभी 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित, यह जी2सी प्लेटफ़ॉर्म आई.सी.ए.पी./डीपीआर योजना, पी.एफ.एम.एस.- सक्षम भुगतान और जियो-रुर्बन ऐप के माध्यम से जियो-टैग की गई संपत्ति ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करता है। हालाँकि नए कार्यों की ऑनबोर्डिंग अब बंद हो गई है, यह प्रणाली तब तक सक्रिय रहती है जब तक सभी विक्रेता भुगतानों का निपटान नहीं हो जाता, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्केलेबल समाधान विकसित करने की असम की क्षमता को दर्शाता है।

असम के लिए अनुकूलित राष्ट्रीय परियोजनाएँ

राज्य-विशिष्ट पहलों के अलावा, एनआईसी असम ने स्थानीय आवश्यकताओं और भाषाई आवश्यकताओं के अनुरूप 12 प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं को सफलतापूर्वक अनुकूलित और कार्यान्वित किया है। ई-ऑफिस पहल ने निदेशालय स्तर तक सभी विभागों में 100% ई-फाइल अपनाई है, 811,640 ई-फाइलें, 4516,764 रसीदें बनाई हैं और 137,787 फाइलों को परिवर्तित करते हुए 1373,667 पत्र जारी किए हैं, जिससे कुशल और पारदर्शी शासन

▼ चित्र 1.5 : असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम-ट्रांस का शुभारंभ करते हुए

▲ चित्र 1.6 : माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सेवा सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया

संभव हुआ है और कहीं भी, कभी भी फाइलों तक पहुँच संभव हुई है। ई-ट्रांसपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म, जिसे सीएम-ट्रांस के नाम से जाना जाता है, असम को 73 संपर्क रहित सेवाओं के साथ परिवहन स्वचालन में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाता है। यह व्यापक प्रणाली स्पीड लिमिटिंग डिवाइस, ई-चालान और ई-डार को एकीकृत करती है। इसमें परिवहन सेवाओं के पूर्ण स्वचालन के साथ-साथ, पायलट पहल के रूप में एम.ओ.आर.टी.एच. की कैशलेस उपचार योजना भी शामिल है।

अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आई.सी.जे.एस.) असम में एक सफल पहल है, जो पुलिस, ई-न्यायालय, ई-कारागार, ई-फ़ोरेंसिक और ई-अभियोजन को एकीकृत करती है, जिसमें चिकित्सा विधिक परीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रणाली (मेडलीएपीआर) भी शामिल है, जिससे 'एक डेटा, एक प्रविष्टि' सिद्धांत के तहत निर्बाध डेटा साझाकरण सुनिश्चित होता है, जिससे त्वरित और पारदर्शी न्याय प्रदान करना सुनिश्चित होता है। जीवन प्रमाण असमिया भाषा समर्थन के साथ बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिसमें 32,708 सफल प्रस्तुतियाँ दर्ज की जाती हैं, जबकि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) एप्लिकेशन 1,115 पंजीकृत परियोजनाओं, 83 पंजीकृत एजेंटों और 405 शिकायतों (262 निपटाई गई) के साथ रियल एस्टेट विनियमन की सुविधा प्रदान करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 35,055 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2,46,78,138 लाभार्थियों को कवर करते हुए 70,86,456 राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.) असम को शिकायत निपटान के लिए पूर्वोत्तर में दूसरे और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रखती है, जबकि नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल 129 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ता है, जो 14.723 मिलियन से अधिक ओपीडी पंजीकरणों को संसाधित करता है और 687 स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। स्पैरो 5,720 ए.पी.ए.आर. पंजीकृत, समीक्षा और स्वीकृत के साथ प्रदर्शन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है, जबकि ई-प्रोक्योरमेंट ने असम में 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से ₹2,96,701 करोड़ मूल्य की 71,057 निविदाओं को सुगम बनाया है। ई-जागृति प्लेटफ़ॉर्म उपभोक्ता संरक्षण को सशक्त बनाता है 7,144 शिकायतें दर्ज की गईं और 4,877 का निपटारा किया गया (68.27% निपटान दर)। ये एनआईसी असम की अंतर-संचालन क्षमता और मानकों को बनाए रखते हुए राज्य-विशिष्ट संदर्भों के लिए राष्ट्रीय समाधानों को अनुकूलित करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र

क्षेत्र की कंप्यूटिंग क्षमता को मज़बूत करने के लिए, पूर्वोत्तर के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र, 4 मेगावाट कुल क्षमता के साथ, एनआईसी और निक्सी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह रणनीतिक बुनियादी ढाँचा विकास क्षेत्रीय डिजिटल क्षमताओं में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। 200 से अधिक सर्वर रैक (400 तक विस्तार योग्य) की क्षमता के साथ, उच्च-स्तरीय कनेक्टिविटी, ऑन-डिमांड क्लाउड बुनियादी ढाँचा, और सुरक्षित डेटा होस्टिंग, प्रसंस्करण और डेटा प्रबंधन के साथ, यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक मज़बूत डिजिटल आधार तैयार करेगा जो ई-गवर्नेंस पहलों की बढ़ती माँगों का समर्थन करेगा।

▼ चित्र 1.7 : राष्ट्रीय डेटा केंद्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र

मुख्य सेवाएँ

निकनेट, एनकेएन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ और वेबकास्टिंग जैसी मुख्य सेवाएँ पूरे राज्य में व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। निकनेट 2003 से असम सरकार की डिजिटल आधारशिला रहा है, जिसका 21,388 नोड्स का व्यापक नेटवर्क चौबीसों घंटे निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। असम सचिवालय के मज़बूत लैन बुनियादी ढाँचे में 5,000 से ज़्यादा नोड्स हैं जिनमें अप्रतिबंधित इंटरनेट बैंडविड्थ और आईपीवी6 अनुपालन है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ 1995 से एनआईसी असम के पोर्टफोलियो का हिस्सा रही हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान अमूल्य साबित हुईं। 2025 (सितंबर तक) में 950 वीडियो कॉन्फ्रेंस और 2024 में 1,619 कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं। राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत ईमेल सेवाओं द्वारा और भी मजबूत किया गया है, जो assam.gov.in और assampolice.gov.in डोमेन पर 50,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को समर्थन प्रदान करती हैं, और एक समर्पित सेवा डेस्क टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से चौतरफा तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। असम में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) उपस्थिति केंद्र 2011 से चालू है, जो 12 कोर नेटवर्क से जुड़ता है और 80G बैंडविड्थ क्षमता और उच्च उपलब्धता प्रणालियों के साथ 10/2.5 जी.बी.पी.एस. बैंडविड्थ प्रदान करता है, जो 64 प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ता है।

क्षेत्रीय अनुप्रयोग सुरक्षा एवं लेखा परीक्षा

जयनगर, गुवाहाटी में स्थित एप्लीकेशन सुरक्षा एवं लेखा परीक्षा के लिए क्षेत्रीय केंद्र आर.ए.एस.ए., एप्लीकेशन सुरक्षा लेखा परीक्षा, भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण सहित व्यापक सेवाएं प्रदान करता है।

निष्कर्ष

एनआईसी असम राज्य सरकार का सबसे विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार बनकर उभरा है, जो प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण को मज़बूत करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल समाधान प्रदान करता है, जो राज्य मुख्यालय से लेकर दूरस्थ ज़िलों तक फैला हुआ है। असम सरकार की अधिकांश आईसीटी पहलों को संभालने, राष्ट्रीय स्तर पर समाधान विकसित करने और जल तरंगिनी जैसे अग्रणी नवाचारों की राज्य केंद्र की उपलब्धि, सरकार और एनआईसी के बीच प्रतिबद्ध साझेदारी की क्षमता को प्रदर्शित करती है। एनआईसी की तकनीकी विशेषज्ञता और राज्य सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा संचालित असम की डिजिटल परिवर्तन यात्रा, अन्य राज्यों के लिए, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और अवसंरचनात्मक परिदृश्यों में, एक प्रेरक मॉडल के रूप में कार्य करती है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी असम राज्य केंद्र
प्रथम तल, कम्पोजिट बिल्डिंग, अंतिम द्वार, दिसपुर
गुवाहाटी, असम - 781006
ईमेल: sio-asm@nic.in, फ़ोन: 0361-2237164